समक्ष परमजीत सिंह न्यायमूर्ति

उदय सिंह और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य- उत्तरदाता

2015 का सीआरआर नंबर 1278

19 मई, 2015

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958-धारा 4-पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र (अनियमित विकास का प्रतिबंध) अधिनियम, 1963-धारा 12-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 313,360 और 361-मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985-धारा 22-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989-धारा 19-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धारा 9-ई-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-धारा 18-परिवीक्षा-जिला और नगर योजनाकार ने शिकायत की कि याचिकाकर्ताओं सहित कई व्यक्ति अनधिकृत कॉलोनी स्थापित करने के लिए सड़कों का निर्माण कर रहे थे और विभाग के निदेशक की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच के साधन तैयार कर रहे थे - निचली अदालत और निचली अपीलीय अदालत ने याचिकाकर्ताओं और अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें एक साल के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई - याचिकाकर्ताओं ने परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के तहत परिवीक्षा पर रिहाई की मांग की। अभिनिर्धारित, कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के प्रावधान और परिवीक्षा अधिनियम दोषी व्यक्ति के सुधार और पुनर्वास के उद्देश्यों को वैधानिक मान्यता देता है - पहली बार अपराध करने वालों को अशिष्ट अपराधी बनने से रोका जाना चाहिए - जिस अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं को सजा सुनाई गई थी वह तकनीकी प्रकृति का था-अपराध का परिमाण गंभीर प्रकृति का नहीं था-अपराधियों का चरित्र बेदाग था-याचिकाकर्ता कृषक थे, शांतिपूर्ण व्यवसाय करते थे-वे पहले ही सजा के कुछ हिस्से से गुजर चुके थे-उन्हें खुद को सुधारने और ईमानदार श्रम द्वारा अपने परिवार का पालन-पोषण करने का अवसर दिया जा सकता था-याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा पर रिहा किया जाना था।

अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली धीरे-धीरे एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है ताकि पहली बार के अपराधियों को कठोर अपराधियों के साथ उनके जुड़ाव के परिणामस्वरूप अशिष्ट अपराधियों में परिवर्तित होने से रोका जा सके यदि उन्हें जेल में कारावास से गुजरना पड़ता है। उद्देश्य दंड के क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप है जो सुझाव देता है कि व्यक्तिगत अपराधियों के सुधार और सुधार के लिए प्रयास किया जाना चाहिए

और प्रतिशोधात्मक न्याय/निवारक सजा का सहारा नहीं लेना चाहिए। आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र यह मानता है कि कोई भी जन्मजात अपराधी नहीं है। अधिकांश अपराध सामाजिक-आर्थिक परिवेश की उपज हैं। संहिता और परिवीक्षा अधिनियम की धारा 360 के प्रावधान सुधार और पुनर्वास के उद्देश्यों को वैधानिक मान्यता देते हैं।

(पैरा 11)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सभी अपराधों में सजा के मामले में बहुत व्यापक विवेकाधिकार विचारण और अपीलीय न्यायालय में निहित है। विवेकाधिकार का प्रयोग विवेक का विषय है न कि कानून का। यह एक सुव्यवस्थित कानून है कि कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में परिवीक्षा अधिनियम और संहिता के प्रावधानों के लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

(पैरा 24)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराधियों का सुधार और पुनर्वास उपरोक्त निर्दिष्ट प्रावधानों के प्रमुख अंश हैं। हालाँकि सजा की समस्या एक चौंका देने वाला मुद्दा है, फिर भी सजा सुनाते समय न्यायालय को इस बात पर गौर करने की आवश्यकता होती है कि किसी दोषी व्यक्ति को जेल भेजे बिना न्याय के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। कई बार सजा में सुधार से संबंधित विधानों को अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों के संज्ञान में नहीं लाया जाता है और इसलिए उन पर विचार नहीं किया जाता है, इसलिए इसका लाभ अपराधियों को नहीं दिया जाता है। यह पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण प्रतीत होता है और भले ही वकील मदद नहीं करता है, न्यायालय को परिवीक्षा अधिनियम या संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों जैसे अधिनियमों में निहित सजा देने के अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए।

(पैरा 25)

इसके अलावा अभिनिर्धारित किया गया कि पूरे मामले और वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जिस अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं को सजा सुनाई गई है, वह तकनीकी प्रकृति का है। याचिकाकर्ता कृषि भूमि के मालिक हैं, हालांकि, उन्हें अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। अन्यथा अपराध करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह उन प्रावधानों का उल्लंघन है जो साधारण कारावास का प्रावधान करते हैं न कि कठोर कारावास का। अपराध की प्रकृति गंभीर नहीं है और अपराधियों का चरित्र बेदाग है और ऐसा भी नहीं है कि यह लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता है। राज्य ने यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया है कि याचिकाकर्ता पिछले दोषी या आदतन अपराधी।याचिकाकर्ता किसान हैं और उनके पास

देखभाल करने के लिए अपने खेत और जानवर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता देहाती ग्रामीण होने के नाते कानून की बारीकियों से अवगत नहीं हैं और बिल्डरों द्वारा लुभाया गया होगा। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता/अपराधी मध्यम आयु वर्ग के हैं और उनके पूर्वजों में कोई दोष नहीं है। वे कृषक हैं, शांतिपूर्ण व्यवसाय करते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए पत्नियां, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य हैं और वे पूरी तरह से कृषि व्यवसाय पर निर्भर हैं । ये उनके पक्ष में राहत देने वाले कारक हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता 19.3.2015 से सजा काट रहे हैं, वे सजा के कुछ हिस्से से गुजरे हैं। मुकदमेबाजी की एक लंबी अवधि और कारावास की छोटी अवधि निश्चित रूप से एक निवारक के रूप में काम करेगी। उन्हें खुद को सुधारने और कृषक के रूप में ईमानदार श्रम द्वारा अपने परिवार का पालन-पोषण करने का अवसर दिया जा सकता है ताकि सामाजिक दायित्वों के हितों को सुरक्षित किया जा सके।

(पैरा 37)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय का झुकाव था कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा सकता है। यह भी संतुष्ट था कि याचिकाकर्ताओं के पास निवास और नियमित व्यवसाय का निश्चित स्थान है। इसलिए, न्यायालय निर्देश देता है कि याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत रिहा किया जाए, और उनकी सजा को बनाए रखने के बजाय यह निर्देश दिया जाए कि उन्हें निचली अदालत के समक्ष एक-एक मुचलके के साथ रिहाई की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने के लिए और इस बीच शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार रखने के लिए बांड करने पर रिहा किया जाए, । याचिकाकर्ता आज से तीन सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष बांड और प्रतिभू प्रस्तुत करेंगे और एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि 1.6.2015 से शुरू होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें 1.6.2015 से उनके प्रस्तुत बांड पर परिवीक्षा पर रिहा किया जाएगा, जैसा कि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं होने पर ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अधीन है। याचिकाकर्ता परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के लाभ के भी हकदार होंगे। दोषसिद्धि के विवादित निर्णय को बरकरार रखा जाता है और सजा के क्रम को उपरोक्त शर्तों में संशोधित किया जाता है।

(पैरा 38)

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता टी पी सिंह,

नवीन शीओरान, डीएजी, हरियाणा

परमजीत सिंह, न्यायमूर्ति

(1) प्रारंभिक सुनवाई के समय, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने योग्यता के आधार पर संशोधन पर जोर नहीं दिया और परिवीक्षा के अनुदान के लिए अपनी

प्रार्थना को सीमित कर दिया। इस प्रकार, प्रस्ताव की सूचना परिवीक्षा के अनुदान तक सीमित जारी की गई थी।

(2) तत्काल याचिका में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (संक्षेप में परिवीक्षा अधिनियम) के तहत याचिकाकर्ताओं के साथ व्यवहार करने के प्रश्न की जांच की जानी चाहिए। वह अपराध, जिसके लिए दोषसिद्धि प्रदान की गई है, वह है जिस पर संहिता की धारा 360 या परिवीक्षा अधिनियम का प्रावधान लागू हो सकता है। मेरे समक्ष सामग्री अपर्याप्त है क्योंकि विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय सजा सुनाने के अपने कार्यों का निर्वहन करने में अक्षम रहे हैं। सजा सुनाने का उद्देश्य अपराधियों को बंद करना और चाबी फेंकना नहीं है। मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि एक आरोपी को सजा सुनाना विवेक का एक संवेदनशील अभ्यास है न कि एक नियमित या यांत्रिक प्रक्रिया। विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय को मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत सजा देने से पहले आवश्यक सामग्री एकत्र करनी चाहिए। अपराधी की सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत कारक बहुत प्रासंगिक हैं, हालांकि व्यवहार में आपराधिक न्यायालय शायद ही सामाजिक परिवेश या अपराधी की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं। भले ही संहिता की धारा 360 या परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया जाता है, यह सजा देने वाले न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पुनर्वास और सुधारात्मक दृष्टिकोण के साथ ऐसे तथ्यों को एकत्र करे जिनका दंड पर असर हो। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील से भी वस्तुतः कोई सहायता नहीं है ।

(3) तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश दिनांक 23.04.2013 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है और एक वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है और पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र (अनियमित विकास का प्रतिबंध) अधिनियम, 1963 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 12 (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 10000 रुपये के जुर्माने के साथ दोषी ठहराया गया और निर्णय दिनांक 19.03.2015 को विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला द्वारा अपील में पारित किया गया है, जिसके तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है, हालांकि, जुर्माने को कार्यवाही की लागत में परिवर्तित कर दिया गया है।

(4) मुझे इस मामले के तथ्यों पर विस्तार से विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें नीचे दिए गए विद्वत न्यायालयों के निर्णयों में पहले ही दोहराया जा चुका है, हालांकि, तत्काल संशोधन के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्य इस आशय के हैं कि जिला और नगर योजनाकार, अंबाला ने दिनांक 28.06.2006 को एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई व्यक्ति (कुल तेरह) एक अनधिकृत कॉलोनी स्थापित करने के लिए सड़कों का निर्माण कर रहे हैं और विभाग के निदेशक से पूर्व अनुमति लिए बिना गांव पंजोखरा की राजस्व सीमा में स्थित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 तक पहुंच के साधन बिछा रहे हैं। यह भी आरोप

लगाया गया था कि अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के तहत अधिसूचना संख्या सीसीपी (एनसीआर/सीएए/2005/1337) दिनांक 11.08.2005 के माध्यम से नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा जारी की गई है। इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच पड़ताल की गई। जांच की परिणति पर, संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट सात व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तुत की गई थी और अन्य को कॉलम नंबर. 2 में दिखाया गया था क्योंकि वे निर्दोष पाए गए थे। निचली अदालत ने दिनांक 20.03.2007 के आदेश के तहत अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आरोप तय किए, जिस पर आरोपी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया। आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कम से कम पाँच गवाहों से पूछताछ की। संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया। सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों को उनके सामने रखा गया था। उन्होंने इससे इनकार किया और अपने झूठे निहितार्थ का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों को बचाव का नेतृत्व करने का अवसर दिया गया था, लेकिन वे कोई सबूत पेश करने में विफल रहे। निचली अदालत ने अभिलेख पर पूरी सामग्री का विश्लेषण करते हुए याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों को अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें उपरोक्त के रूप में सजा सुनाई। निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला के समक्ष अपील की, जिसे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ खारिज कर दिया गया है। इसलिए, यह पुनरीक्षण याचिका।

(5) मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के साथ-साथ राज्य के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि अपराध तकनीकी प्रकृति का है। याचिकाकर्ताओं को भूमि के मालिक होने के नाते इसका उपयोग करने का अधिकार है, हालांकि, अधिसूचना के कुछ उल्लंघन को देखते हुए, जिसके तहत उनकी भूमि को नियंत्रित क्षेत्र के तहत लाया गया है, उन पर मुकदमा चलाया गया और नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा सजा सुनाई गई। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि के निर्णय और योग्यता के आधार पर सजा के आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त कारण हैं, फिर भी वह चुनौती को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 और संहिता की धारा 360 में निहित प्रावधानों की प्रयोज्यता पर विचार न करने तक सीमित कर रहे हैं। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि हरियाणा राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर परिवीक्षा अधिनियम लागू होता है। याचिकाकर्ता देहाती ग्रामीण हैं और कृषि व्यवसाय करते हैं और अपने खेत और जानवरों की देखभाल करते हैं। उन्हें अपने परिवार की भी देखभाल करनी पड़ती है।

(7) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय परिवीक्षा अधिनियम में या संहिता की धारा 360 के तहत निहित परोपकारी प्रावधानों पर विचार करे। राज्य के वकील ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि परिवीक्षा अधिनियम हरियाणा राज्य में लागू है। इस न्यायालय के पास साक्ष्य की पुनः सराहना करने का सीमित अधिकार क्षेत्र है, जब नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। यह अदालत तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब कानून और निर्णय की त्रुटि हो और सजा का आदेश विकृत हो।

(8) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार किया है।

(9) पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों के आलोक में, निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः -

"(i) क्या निचली अदालतें सजा सुनाने से पहले संहिता के प्रावधानों या परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता की जांच करने के लिए बाध्य हैं?

(ii) आपराधिक पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की क्या गुंजाइश है, क्या उच्च न्यायालय को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्य करना चाहिए और उसकी धारा 3, 4 या 6 के तहत आदेश पारित करना चाहिए और परिवीक्षा देने में अदालतों की क्या सीमाएँ हैं?

(10) निर्धारण के लिए प्रश्नों की जांच करने से पहले, प्रासंगिक धाराओं को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जो कि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3,4,5,6,11,18 और 19 और संहिता की धारा 360 और 361 हैं, जो निम्नानुसार हैंः -

"**3. चेतावनी के बाद कुछ अपराधियों को रिहा करने की अदालत की शक्ति**:- जब किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 379 या धारा 380 या धारा 404 या धारा 420 या धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन दो वर्ष से अधिक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं होती है और जिस न्यायालय द्वारा व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, उसकी राय है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना समीचीन है, तब, उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे किसी दंड की सजा देने या धारा 4 के अधीन अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने के स्थान पर दंडनीय चेतावनी के बाद उसे रिहा कर सकता है। **स्पष्टीकरण**-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि में इस धारा या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई पूर्व आदेश सम्मिलित होगा।

4. अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर कुछ अपराधियों को रिहा करने की अदालत की शक्तिः- (1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और न्यायालय जिसके द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, की राय है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तो, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायालय उसे तुरंत किसी दंड के लिए सजा सुनाने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि उसे जमानत के साथ या उसके बिना मुचलके में प्रवेश करने पर रिहा किया जाए और ऐसी अवधि, तीन साल से अधिक नहीं, के दौरान बुलाए जाने पर सजा प्राप्त करने के लिए, जैसा कि अदालत निर्देश दे, और इस बीच शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के लिएः बशर्ते कि अदालत किसी अपराधी की ऐसी रिहाई का निर्देश तब तक नहीं देगी जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि अपराधी या उसकी जमानत, यदि कोई हो, का उस स्थान पर निवास या नियमित व्यवसाय का एक निश्चित स्थान है जिस पर अदालत अधिकारिता का प्रयोग करती है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बांड में प्रवेश करता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व न्यायालय मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, तो न्यायालय, यदि उस की राय है कि अपराधी और जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है, तो इसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकता है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अपराधी आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में ऐसी अवधि के दौरान रहेगा, जो एक वर्ष से कम नहीं है, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह अपराधी के उचित पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी से, उसे रिहा किए जाने से पूर्व, प्रतिभू के साथ या उसके बिना, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों और निवास, मादक पदार्थों से परहेज़ या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का पालन करने के लिए, जो न्यायालय, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसी अपराध की याचिका या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए अधिरोपित करने के लिए उपयुक्त समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी को आदेश के नियमों और शर्तों की व्याख्या करेगा और प्रत्येक अपराधी, प्रतिभू, यदि कोई हो,

और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति तुरंत प्रस्तुत करेगा।

5. रिहा किए गए अपराधियों से मुआवजे और लागत का भुगतान करने की अपेक्षा करने की अदालत की शक्ति:-

(1) धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराधी की रिहाई का निदेश देने वाला न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो उसी समय उसे भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक और आदेश दे सकता है -

(क) ऐसा प्रतिकर जो न्यायालय अपराध के कारण किसी व्यक्ति को हुई हानि या क्षति के लिए उचित समझता है; और

(ख) कार्यवाहियों की ऐसी लागत जो न्यायालय उचित समझता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन संदत्त किए जाने का आदेश दी गई रकम संहिता की धारा 386 और 387 के उपबंधों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकती है।

(3) उसी मामले से उत्पन्न होने वाले किसी वाद का विचारण करने वाला सिविल न्यायालय, जिसके लिए अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है, हर्जाना देने में उपधारा (1) के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा।

6. इक्कीस वर्ष से कम आयु के अपराधियों के कारावास पर प्रतिबंध:— (1) जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति कारावास (लेकिन आजीवन कारावास से नहीं) से दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो वह न्यायालय जिसके द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसे कारावास की सजा नहीं देगा, जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, धारा 3 या धारा 4 के तहत उसके साथ व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, और यदि अदालत अपराधी को कारावास की कोई सजा सुनाती है, तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगी।

(2) स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराधी के साथ धारा 3 या धारा 4 के अधीन व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा और अपराधी के चरित्र और शारीरिक और मानसिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट, यदि कोई हो, और उसके पास उपलब्ध किसी अन्य जानकारी पर विचार करेगा।

11. अधिनियम, अपील और पुनरीक्षण और अपील और पुनरीक्षण में न्यायालयों की शक्तियों के अधीन आदेश देने के लिए सक्षम न्यायालय:-

(1) संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश, अपराधी को विचारण करने और कारावास की सजा देने के लिए सशक्त किसी न्यायालय द्वारा और जब मामला अपील या पुनरीक्षण पर उसके समक्ष आता है तो उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है।

(2) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जहां अपराधी (उच्च न्यायालय से भिन्न) का विचारण करने वाले किसी न्यायालय द्वारा धारा 3 या धारा 4 के अधीन कोई आदेश दिया जाता है, वहां उस न्यायालय में अपील की जाएगी, जिसमें अपील सामान्य रूप से पूर्व न्यायालय के दंडादेशों से संबंधित होती है।

(3) किसी भी मामले में जहां इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अपराध करने का दोषी पाया जाता है और न्यायालय, जिसके द्वारा वह दोषी पाया जाता है, धारा 3 या धारा 4 के तहत उसके साथ व्यवहार करने से इनकार करता है और जुर्माने के बिना कारावास या कारावास की सजा देता है, जिसमें से कोई अपील नहीं होती है अपील को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो, संहिता या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, जिस अदालत में अपील आमतौर पर पूर्व अदालत के वाक्यों से होती है, वह अदालत, अपने स्वयं के प्रस्ताव से या दोषी व्यक्ति या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उस पर किए गए आवेदन पर, मामले के रिकॉर्ड की मांग कर सकता है और जांच कर सकता है और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है।

(4) जब किसी अपराधी के संबंध में धारा 3 या धारा 4 के अधीन कोई आदेश दिया गया है, तो अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है और उसके स्थान पर ऐसे अपराधी को विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता हैः बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय उस न्यायालय द्वारा, जिसके द्वारा अपराधी को दोषी पाया गया था, अधिरोपित नहीं करेगा।

18. कुछ अधिनियमों के संचालन को बचाना - इस अधिनियम की कोई बात सुधारात्मक स्कूल अधिनियम, 1897 (1897 का 8) की धारा 31 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

19. संहिता की धारा 562 कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगी:- - संहिता की धारा 562 की धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उन राज्यों या उनके भागों पर लागू नहीं होगी जिनमें यह अधिनियम लागू किया गया है।

धारा 360 और 361 Cr.P.C निम्नानुसार हैंः -

"**360. अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर या चेतावनी के बाद रिहा करने का आदेश:-** - (1) जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति केवल जुर्माने या सात वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, या जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति या कोई महिला किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, और अपराधी के खिलाफ कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं होती है, यदि यह उस न्यायालय को प्रतीत होता है जिसके समक्ष वह दोषी ठहराया गया है, अपराधी की आयु, चरित्र या पूर्ववृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, और जिन परिस्थितियों में अपराध किया गया था, कि यह समीचीन है कि अपराधी को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए, तो न्यायालय उसे किसी भी सजा के लिए एक बार में सजा सुनाने के बजाय, निर्देश दे सकता है कि उसे मुचलके के साथ या बिना मुचलके में प्रवेश करने पर रिहा किया जाए, उपस्थित होने और प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि (तीन वर्ष से अधिक नहीं) के दौरान बुलाए जाने पर सजा और बीच में अच्छा व्यवहार रखने का निर्देश दे सकता हैः परन्तु जहां कोई प्रथम अपराधी द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा, जो उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सशक्त नहीं है, दोषी ठहराया जाता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, वह उस आशय के लिए अपनी राय दर्ज करेगा और अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अग्रेषित करते हुए या उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानत लेते हुए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को कार्यवाही प्रस्तुत करेगा, जो उप-धारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से मामले का निपटारा करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) द्वारा उपबंधित प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को कार्यवाहियां प्रस्तुत की जाती हैं, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा दंडादेश पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो वह पारित कर सकता है या कर सकता है यदि मामले की मूल रूप से उसके द्वारा सुनवाई की गई हो, और यदि वह समझता है कि किसी बिंदु पर आगे की जांच या अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है, तो वह ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकता है या ऐसी जांच या साक्ष्य बनाने या लेने का निर्देश दे सकता है।

(3) किसी ऐसे मामले में जिसमें किसी व्यक्ति को चोरी, भवन में चोरी, बेईमानी से गबन, धोखाधड़ी या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन किसी अपराध के लिए दो वर्ष से अधिक के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध के साथ दंडनीय ठहराया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं होती है, न्यायालय, जिसके समक्ष वह इस प्रकार दोषी ठहराया गया है, अपराधी की आयु, चरित्र, पूर्ववृत्तियों या शारीरिक या मानसिक स्थिति और अपराध की तुच्छ प्रकृति या किसी भी विस्तारित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत अपराध किया गया था, उसे किसी भी सजा की सजा देने के बजाय, उसे उचित चेतावनी के बाद रिहा कर सकता है।

(4) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय किया जा सकता है।

(5) जब किसी अपराधी के संबंध में इस धारा के अधीन कोई आदेश दिया गया है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, अपील करने पर जब ऐसे न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, या अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है, और उसके स्थान पर ऐसे अपराधी को विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता हैः बशर्ते कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय इस उप-धारा के अधीन उस न्यायालय द्वारा, जिसके द्वारा अपराधी को दोषी ठहराया गया था, अधिरोपित किए जाने से अधिक दंड नहीं करेगा।

(6) धारा 121,124 और 373 के उपबंध, जहां तक संभव हो, इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में दिए गए प्रतिभूओं के मामले में लागू होंगे।

(7) न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन अपराधी की रिहाई का निर्देश देने से पहले संतुष्ट होगा कि किसी अपराधी या उसके मुचलकेदार (यदि कोई हो) का उस स्थान पर निवास या नियमित व्यवसाय का एक निश्चित स्थान है जिसके लिए न्यायालय कार्य करता है या जिसमें अपराधी के शर्तों के पालन के लिए नामित अवधि के दौरान रहने की संभावना है।

(8) यदि वह न्यायालय जिसने अपराधी को दोषी ठहराया है, या कोई न्यायालय जो अपराधी के साथ उसके मूल अपराध के संबंध में व्यवहार कर सकता था, संतुष्ट है कि अपराधी अपनी पहचान की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहा है, तो वह उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है।

(9) एक अपराधी, जब ऐसे किसी वारंट पर पकड़ा जाता है, तो उसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष तुरंत लाया जाएगा, और ऐसा न्यायालय या तो उसे तब तक अभिरक्षा में भेज सकता है जब तक कि मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है या उसे सजा के लिए उपस्थित होने पर पर्याप्त मुचलके के साथ जमानत पर स्वीकार कर सकता है और ऐसा न्यायालय मामले की सुनवाई के बाद सजा सुना सकता है।

(10) इस धारा की कोई बात अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) या बाल अधिनियम, 1960 (1960 का 60) या युवा अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी।

361. **कुछ मामलों में विशेष कारण दर्ज किए जाने चाहिए:-** जहां किसी मामले में न्यायालय, (क) धारा 360 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंधों के अधीन; या
(ख) बाल अधिनियम, 1960 (1960 का 60) के अधीन या युवा अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति से व्यवहार कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया है, वहां वह अपने निर्णय में ऐसा न करने के विशेष कारणों को अभिलिखित करेगा।

पुन. प्रश्न संख्या 1: -

(11) भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली धीरे-धीरे एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है ताकि पहली बार के अपराधियों को कठोर अपराधियों के साथ उनके जुड़ाव के

परिणामस्वरूप अशिष्ट अपराधियों में परिवर्तित होने से रोका जा सके यदि उन्हें जेल में कारावास से गुजरना पड़ता है। उद्देश्य दंड के क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप है जो सुझाव देता है कि व्यक्तिगत अपराधियों के सुधार और सुधार के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और प्रतिशोधात्मक न्याय/निवारक सजा का सहारा नहीं लेना चाहिए। आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र यह मानता है कि कोई भी जन्मजात अपराधी नहीं है। अधिकांश अपराध सामाजिक-आर्थिक परिवेश की उपज हैं। संहिता की धारा 360 और परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान सुधार और पुनर्वास के उद्देश्यों को वैधानिक मान्यता देते हैं।

(12) 1957 के विधेयक संख्या 79 के लिए उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में पारित किया गया था, निम्नानुसार कहता है: -

"(1) अपराधियों को कारावास की सजा देने के बजाय अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर रिहा करने का प्रश्न समय-समय पर विचाराधीन रहा है। 1931 में, भारत सरकार ने अपराधियों के परिवीक्षा विधेयक का एक मसौदा तैयार किया और इसे तत्कालीन स्थानीय सरकारों को उनके विचारों के लिए वितरित किया। हालाँकि, अन्य अधिक महत्वपूर्ण मामलों के साथ पूर्व-व्यवसाय के कारण, विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। बाद में 1934 में, भारत सरकार ने प्रांतीय सरकारों को सूचित किया कि उस समय केंद्रीय कानून बनाए जाने की कोई संभावना नहीं थी और प्रांतों को स्वयं इस तरह के कानून बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तदनुसार कुछ प्रांतों ने अपने स्वयं के परिवीक्षा कानून बनाए।

(2) हालांकि, कई राज्यों में कोई अलग परिवीक्षा कानून नहीं हैं। यहां तक कि उन राज्यों में भी जहां परिवीक्षा कानून हैं, वे समान नहीं हैं और न ही वे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इस बीच, अपराधी को जेल जीवन के हानिकारक प्रभावों के अधीन किए बिना समाज के एक उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्य के रूप में सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है। देश में परिवीक्षा प्रणाली में व्यापक रुचि को देखते हुए, इस प्रश्न की फिर से जांच की गई है और इस विषय पर एक केंद्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव है जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

(3) कुछ निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में चेतावनी के बाद अपराधी को रिहा करने के लिए न्यायालयों को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है। अदालतों को सभी उपयुक्त मामलों में परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है, एक अपराधी जिसे ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के संबंध में, उनके कारावास पर प्रतिबंध लगाते हुए विशेष प्रावधान किया गया है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, अपराधी परिवीक्षा अधिकारियों की देखरेख में रहेंगे ताकि उनमें सुधार किया जा सके और वे समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें। विधेयक इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(13) संहिता के प्रावधान भी ऐसे ही हैं। संहिता की धारा 360 (10) में विशेष रूप से कहा गया है कि इस धारा की कोई भी बात अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 या युवा अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

(14) ऊपर निकाले गए उद्देश्यों और कारणों के आलोक में, परिवीक्षा अधिनियम और संहिता की धारा 360 के "परिवीक्षा" और "योजना" के अर्थ की जांच करना उचित होगा।

परिवीक्षा का अर्थ और यह अवधारणा कैसे महत्वपूर्ण हो जाती हैः-

(15)"परिवीक्षा" शब्द लैटिन शब्द "प्रोबेयर" से लिया गया है, जिसका अर्थ है परीक्षण करना या साबित करना। व्युत्पत्ति के अनुसार, परिवीक्षा का अर्थ है "मैं अपनी योग्यता साबित करता हूं।" यह एक उपचार उपकरण है और अभिरक्षा उपाय का एक विकल्प है जिसका उपयोग आम तौर पर विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति को जेल भेजने के बजाय दोषी ठहराया जाता है, तो उसे सुधार करने का मौका दिया जा सकता है। एक उपचार उपाय के रूप में एक अभियुक्त/दोषी को सुधार का मौका दिया जाना चाहिए, जिसे वह जेल में कैद होने और कठोर अपराधियों के साथ सहयोग करने की स्थिति में खो सकता है। सजा के नए रूप में आधुनिक दंडात्मक दृष्टिकोण अभियुक्त-दोषी के सर्वोत्तम हित में समाज की जरूरतों को संतुलित करने के उद्देश्य से है जैसे कि चेतावनी पर रिहाई, अच्छे आचरण की परिवीक्षा, 21 वर्ष या उससे अधिक के अपराधियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए मुआवजा और लागत और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट। अध्ययन से पता चलता है कि कारावास रिहाई के बाद सामान्य समाज में दोषी की पुनः समायोजन करने की क्षमता को कम कर देता है और पेशेवर अपराधियों के साथ जुड़ाव अक्सर अवांछनीय परिणामों की ओर ले जाता है।

संहिता की योजनाः -

(16) भारत में 1931 में भारत सरकार ने अपराधी विधेयक का एक मसौदा तैयार किया, लेकिन इसके बाद 1934 में यह समाप्त हो गया, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लेख किया गया है, यहां तक कि कुछ प्रांतों ने भी अपने स्वयं के कानून बनाए। अंतत: स्वतंत्रता के बाद 1958 में परिवीक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। यहां तक कि 1898 की पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भी परिवीक्षा के संबंध में धारा 562 मौजूद थी। इसके बाद नई संहिता में, जैसा कि 1974 में संशोधित किया गया था, धारा 360 अच्छे आचरण के परिवीक्षा से भी संबंधित है। धारा 361 न्यायालयों के लिए परिवीक्षा के हितकारी प्रावधानों का लाभ न देने के लिए कारण निर्दिष्ट करना अनिवार्य बनाती है। यदि हम परिवीक्षा अधिनियम और संहिता की धारा 360 की योजनाओं की तुलना करते हैं, तो यह स्पष्ट होगा कि परिवीक्षा अधिनियम में परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है जो न्यायालय को सजा-पूर्व रिपोर्ट देंगे और परिवीक्षा की अवधि के दौरान अभियुक्त दोषी की निगरानी भी करेंगे। परिवीक्षा अधिनियम की धारा 18 में विशेष रूप

से यह प्रावधान किया गया है कि जहां परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, वहां संहिता की धारा 360 (पुरानी संहिता की धारा 562) के प्रावधानों को बाहर रखा गया है।

(17) इशर दास बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक कानून का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने से अधिक सुधार करना है। एक अभियुक्त को कठोर अपराधियों के साथ जेल में रखने के बजाय, न्यायालय अच्छे व्यवहार के वादे पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आदेश दे सकता है और परिवीक्षा के दौरान पर्यवेक्षण का आदेश भी दे सकता है। परिवीक्षा अच्छे व्यवहार के वादे पर एक अपराधी की सशर्त रिहाई है।

परिवीक्षा अधिनियम की योजनाः -

(18) परिवीक्षा अधिनियम को छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है -

(i) धारा 1 परिवीक्षा अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है जबकि धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है;

(ii) परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 से 12 बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये प्रावधान 'परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए न्यायालय की भूमिका' से संबंधित हैं;

(iii) धारा 13 से 16 'परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका' से संबंधित है;

(iv) धारा 17 नियम बनाने के लिए सरकार की शक्ति से संबंधित है;

(v) धारा 18 कुछ अधिनियमों के संचालन को बचाने से संबंधित है; और

(vi) धारा 19 कुछ राज्यों में परिवीक्षा अधिनियम के आवेदन से संबंधित है।

(19) रतन लाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि परिवीक्षा अधिनियम दंडविज्ञान के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदार प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील पत्थर है। परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का अंतर्निहित उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह है कि एक अभियुक्त व्यक्ति को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए जिसे वह जेल में कैद होने और कठोर अपराधियों के साथ सहयोग करने की स्थिति में खो देगा।

(20) मुसादन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि परिवीक्षा अधिनियम एक सामाजिक विधान है जिसका उद्देश्य किशोर अपराधियों को सुधारना है ताकि सरकार द्वारा उन्हें शिक्षात्मक और सुधारात्मक व्यवहार प्रदान करके उन्हें कठोर अपराधी बनने से रोका जा सके।

(21) परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 से 12 में अपराधी को या तो चेतावनी देने पर या अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने की प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। परिवीक्षा अधिनियम में उल्लिखित पाँच पहलू इस प्रकार हैंः

1. चेतावनी (धारा 3);

2, अच्छे आचरण का प्रोबेशन (धारा 4)

3. मुआवजा और लागत (धारा 5)

4. 21 वर्ष से कम आयु के अपराधी (धारा 6 (1))

5. परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट (धारा 6 (2))

(22) यहां तक कि परिवीक्षा अधिनियम की योजना पर एक सरसरी नज़र भी स्पष्ट रूप से न्यायालयों को सौंपी गई विशिष्ट भूमिका का संकेत देती है। विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय को विशेष रूप से परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता की जांच करने की आवश्यकता है। परिवीक्षा अधिनियम की धारा 6 (2) में यह परिकल्पना की गई है कि 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए यदि अपराध इतना गंभीर नहीं है कि आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा हो। अपराध करने की तिथि पर अपराधी की आयु की गणना की जानी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यदुराज सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसा ही निर्णय दिया है उन सभी मामलों में जहां अभियुक्त की आयु 21 वर्ष से कम है, न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मांगेगा। यदि न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों में अपराधी को परिवीक्षा का लाभ देना वांछनीय नहीं होगा, तो न्यायालय ऐसा करने के कारणों को दर्ज करके कारावास की सजा दे सकता है। न्यायालय का यह देखने का दायित्व है कि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 लागू होती है या नहीं। इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय को परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगानी चाहिए । इसलिए, जब अपराधी की आयु 21 वर्ष से कम हो तो परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट अनिवार्य है। इसके अलावा, निचली अदालत और अपीलीय अदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए, जिसमें अपराध की प्रकृति और चरित्र, अपराधी की शारीरिक और मानसिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक वातावरण जिसमें से अपराधी आता है, शामिल हैं।

(23) महात्मा गाँधी ने कहा था, "पाप से नफरत करो, पापी से नहीं" और "सत्य कभी भी उस कारण को नुकसान नहीं पहुँचाता जो न्यायपूर्ण हो।"

(24) सभी अपराधों में सजा के मामले में बहुत व्यापक विवेकाधिकार विचारण और अपीलीय न्यायालय में निहित है। विवेकाधिकार का प्रयोग विवेक का विषय है न कि कानून का। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि कोई भी अधिकार के मामले में परिवीक्षा अधिनियम और संहिता के प्रावधानों के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। तो कमांडेंट 20 बीएन आईटीबी पुलिस बनाम संजय बिनजोआ में अभिनिर्धारित किया गया है यहां तक कि परिवीक्षा अधिनियम में भी यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यह किस अपराध में लागू होता है और किन अपराधों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

(25) उचित सजा देने से पहले, न्यायालय को कम से कम अपराध के उद्देश्य, अपराध की भयावहता, अपराधी की उम्र, चरित्र और अपराधी की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, परिवीक्षा अधिनियम और संहिता के प्रावधान, जो परिवीक्षा से संबंधित हैं, सजा के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार निरोध से सुधार और अपराध से अपराधी पर जोर देते हैं। अपराधियों का सुधार और पुनर्वास उपरोक्त निर्दिष्ट प्रावधानों के प्रमुख बिंदु हैं। हालाँकि सजा की समस्या एक चौंका देने वाला मुद्दा है, फिर भी सजा सुनाते समय न्यायालय को इस बात पर गौर करने की आवश्यकता होती है कि किसी दोषी व्यक्ति को जेल भेजे बिना न्याय के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। कई बार सजा में सुधार से संबंधित विधानों को अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों के संज्ञान में नहीं लाया जाता है और इसलिए उन पर विचार नहीं किया जाता है, इसलिए इसका लाभ अपराधियों को नहीं दिया जाता है। यह पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण प्रतीत होता है और भले ही वकील मदद नहीं करता है, न्यायालय को परिवीक्षा अधिनियम या संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों जैसे अधिनियमों में निहित सजा देने के अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। इस संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने वेद प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः -

.....भले ही धारा 360, दंड प्रक्रिया संहिता को आकर्षित नहीं किया जाता है, यह सजा सुनाने वाले न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे तथ्यों को एकत्र करने के लिए पर्याप्त सक्रिय हो, जो पुनर्वासकारी झुकाव के साथ सजा पर असर डालते हैं। वर्तमान मामले में ऐसी सामग्रियों की अनुपस्थिति ने हमें वकील से भी बहुत कम सहायता दी है। वास्तव में, बार के सदस्य भी इन विधायी प्रावधानों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं जो एक अपराधी के साथ इस तरह से व्यवहार करने से संबंधित हैं कि वह एक गैर-अपराधी बन जाता है। हम इस पर जोर देते हैं क्योंकि सजा में सुधार से संबंधित कानूनों को 'छोटे अधिनियम' के रूप में माना गया है और इसलिए, इसका बहुत कम परिणाम है। यह एक पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण है और भले ही बार मदद नहीं करता है, बेंच को दंडादेश देने के मानवीय मिशन को पूरा करना चाहिए जो ऐसे अधिनियमों में निहित है जैसे कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम "

(26) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित न्यायालय सजा सुनाने से पहले संहिता या परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता की जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

(27) अन्यथा भी परिवीक्षा पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए बहुत फायदेमंद होगी जहां जेलों में अक्सर भीड़ होती है। अन्यथा मौजूदा सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में अपराधियों को सामान्य समाज में वापस लाना भी आवश्यक है। परिवीक्षा अधिनियम का उद्देश्य यह नहीं है कि सभी अपराधियों को परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन यदि न्यायालय को लगता है कि कोई अपराधी जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है तो न्यायालय निर्णय में विशेष कारण दर्ज करके ऐसा करेगा।

(28) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, प्रश्न संख्या (i) का उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है।

प्रश्न (ii)

(29) निम्नलिखित न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करते हुए इस न्यायालय की अधिकारिता बहुत सीमित है। यह न्यायालय तब तक साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं कर सकता जब तक कि कोई विकृति न हो।

(30) दुली चंद बनाम दिल्ली प्रशासन में आपराधिक पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय की अधिकारिता को लागू करने के दायरे की जांच की गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को निष्कर्ष की विकृति के अभाव में साक्ष्य की पुनः सराहना नहीं करनी चाहिए।

(31) उड़ीसा राज्य बनाम नकुला साहू और अन्य मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, जब विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने वाले तथ्य या विधि की कोई त्रुटि नहीं थी।

(32) केरल राज्य बनाम पुट्टमन इल्लथ जत्थावेदन नम्बूदिरी में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता न्याय की विफलता को सुधारने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली पर्यवेक्षी अधिकारिता में से एक है। लेकिन उक्त पुनरीक्षण शक्ति को अपीलीय न्यायालय की शक्ति के बराबर नहीं माना जा सकता है और न ही इसे दूसरे अपीलीय अधिकार क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है।

(33) वेंकटेसन बनाम रानी के मामले में पैरा 7 में दिए गए निर्णय पर विचार करने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

"7. उपर्युक्त विचार से यह पता चलता है कि बरी किए जाने के आदेश की जांच करते समय उच्च न्यायालयों की पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता अत्यंत संकीर्ण है और इसका प्रयोग केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां विचारण न्यायालय ने विधि या प्रक्रिया की स्पष्ट त्रुटि की थी या प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य की अनदेखी और उपेक्षा की थी जिससे न्याय की हानि हुई थी। साक्ष्य की पुनः प्रशंसा एक ऐसी कवायद है जिससे उच्च न्यायालय को बचना चाहिए संहिता के अधीन अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के आदेश का परीक्षण करना। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि सीमित मापदंडों के भीतर, उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप उचित है, तो कार्रवाई का एकमात्र तरीका जो अपनाया जा सकता है, वह है बरी करने के फैसले को दरकिनार करने के बाद

फिर से सुनवाई का आदेश देना। जैसा कि संहिता की धारा 401 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि उच्च न्यायालय में बरी किए जाने के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने की कोई शक्ति निहित नहीं है।

(34) कई निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रखे गए विधि के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है। वर्तमान मामले में नीचे की अदालतें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर विचार करने में विफल रही हैं जो हरियाणा राज्य में लागू है, वैधानिक प्रावधानों पर विचार न करने के परिणामस्वरूप न्याय का घोर गर्भपात हुआ है, सजा सुनाने से पहले संहिता और परिवीक्षा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों पर कम से कम विचार करना । इस संबंध में निचली अदालतों के फैसले में स्पष्ट अवैधता मौजूद है। परिवीक्षा अधिनियम की धारा 11 (1) को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए उचित आदेश पारित करने के लिए सक्षम है।

संहिता और परिवीक्षा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुप्रयोग के संबंध में न्यायालयों की सीमाः-

(35) कुछ अधिनियम विशेष रूप से संहिता की धारा 360 और परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों जैसे कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 22, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 19, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 9-ई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 18 आदि के लागू होने पर रोक लगाते हैं। यह कोई विस्तृत सूची नहीं है। हालांकि, आगे के विवरण में जाना प्रासंगिक नहीं होगा, इसे संबंधित अपराधों से जुड़े मामले में देखा जाएगा। यदि किसी विशेष अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रतिबंध है, तो ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। परिवीक्षा अधिनियम की धारा 19 को ध्यान में रखते हुए जहां परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, संहिता के प्रासंगिक प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(36) अतः प्रश्न सं. (ii) तदनुसार उत्तर दिया जाता है।

निष्कर्षः-

(37) सम्पूर्ण विवरण और वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जिस अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं को सजा सुनाई गई है, वह तकनीकी प्रकृति का है। याचिकाकर्ता कृषि भूमि के मालिक हैं, हालांकि, उन्हें अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। अन्यथा अपराध करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह उन प्रावधानों का उल्लंघन है जो साधारण कारावास का प्रावधान करते हैं

न कि कठोर कारावास का। अपराध की प्रकृति गंभीर नहीं है और अपराधियों का चरित्र बेदाग है और ऐसा भी नहीं है कि यह लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता है। राज्य ने यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया है कि याचिकाकर्ता पिछले दोषी या आदतन अपराधी हैं। याचिकाकर्ता कृषक होते हैं और उनके पास देखभाल के लिए अपने खेत और जानवर होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता देहाती ग्रामीण होने के नाते कानून की बारीकियों से अवगत नहीं हैं और बिल्डरों द्वारा लुभाया गया होगा। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता/अपराधी मध्यम आयु वर्ग के हैं और उनके पूर्वजों में कोई दोष नहीं है। वे कृषक हैं, शांतिपूर्ण व्यवसाय करते हैं। उनके पास रखने के लिए पत्नियाँ, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य हैं और वे पूरी तरह से कृषि व्यवसाय पर निर्भर हैं। ये उनके पक्ष में छुटकारे देने वाले कारक हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता 19.03.2015 से सजा काट रहे हैं, वे सजा के कुछ हिस्से से गुजरे हैं। मुकदमेबाजी की एक लंबी अवधि और कारावास की छोटी अवधि निश्चित रूप से एक निवारक के रूप में काम करेगी। उन्हें खुद को सुधारने और कृषक के रूप में ईमानदार श्रम द्वारा अपने परिवार का पालन-पोषण करने का अवसर दिया जा सकता है ताकि सामाजिक दायित्वों के हितों को सुरक्षित किया जा सके।

(38) मेरा झुकाव है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा सकता है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि याचिकाकर्ताओं के पास निश्चित निवास स्थान और नियमित व्यवसाय है। इसलिए, मैं निर्देश देता हूं कि याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत रिहा किया जाए, और उनकी सजा को बनाए रखने के बजाय निर्देश दिया जाए कि उन्हें निचली अदालत के समक्ष एक-एक मुचलके के साथ मुचलका दायर करने पर रिहा किया जाए, रिहाई की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होना और सजा प्राप्त करना और इस बीच शांति बनाए रखना और अच्छा व्यवहार करना। याचिकाकर्ता आज से तीन सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष बांड और प्रतिभू प्रस्तुत करेंगे और एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि 01.06.2015 से शुरू होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उन्हें विचारण न्यायालय/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अधीन, उनके प्रस्तुत बांड पर 01.06.2015 से प्रोबेशन पर रिहा कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के लाभ के भी हकदार होंगे। दोषसिद्धि के विवादित निर्णय को बरकरार रखा जाता है और सजा के क्रम को उपरोक्त शर्तों में संशोधित किया जाता है।

(39) पुनरीक्षण याचिका का तदनुसार निपटान किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा